



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 1995/श्रावण 5, 1917

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 1995/SRAVANA 5, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1995

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के आई बी बी के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच पड़ताल—अन्तिम निष्कर्ष ।

सं. 14/50/93—टीपीडी एडोडी.—इसका संबंध वर्ष 1982 में यथासंघाधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 ने है ।

अन्तिम उपाय

1. नियमों के अन्तर्गत यथापरिभाषित नामोद्विष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी कहा जाएगा) ने चीन मूल के आइमांबुटाइन वेन्जीन (जिसे इसके पश्चात आई बी बी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच पड़ताल के प्रारम्भिक निष्कर्ष दिनांक 30 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं. 14/50/93—टीपीडी के तहत अधिसूचित कर दिए हैं ।

क्रियाविधि

2. प्राधिकारी ने जांच के अधीन सभी कंपनियों को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे प्रारम्भिक निष्कर्षों पर अपने विचार प्रेषित करें तथा मौखिक रूप से सुने जाने के लिए आवेदन करें तथा प्रस्तुत आंकड़ों के स्थल-सत्यापन में सहयोग करें । प्रारम्भिक निष्कर्षों की एक प्रथिम प्रति की इस अनुरोध के साथ भेजते हुए कि निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाए कि वे प्राधिकारी को प्राथमिक निष्कर्षों पर अपने विचार व्यक्त करें तथा आंकड़ों के प्रमाणन में सहयोग करें इसके अतिरिक्त संबंधित निर्यातक देश के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को एक मौखिक नोट भी भेजा गया ।

3. नामोद्विष्ट प्राधिकारी को प्रारम्भिक निष्कर्षों पर याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी दोनों के विचार प्राप्त हुए हैं । प्रारम्भिक निष्कर्षों पर भारत में आयातकों के अलावा चीन जनवादी गणराज्य के किसी निर्यातक ने अपने विचार नहीं भेजे हैं ।

4. निर्यातकों, आयातकों और याचिकाकर्ताओं को 6 फरवरी, 1995 को आयोजित लोक सुनवाई में भी, प्रारम्भिक निष्कर्षों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया

था। चीन जनवादी गणराज्य के दिल्ली स्थित राजदूतावास को 13 जनवरी, 1995 को एक मौखिक नोट भेजकर एक अनुरोध किया गया था कि वे इस लोकसुनवाई में भाग लेने के लिए संबंधित निर्यातकों को सूचित कर दें। लेकिन इस लोकसुनवाई में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों तथा निम्नलिखित आयातकों ने ही भाग लिया:—

1. मैसर्स चेमिनॉर इग्स, हैदराबाद,
2. सी वेल इग्स प्रा. लि., हैदराबाद,
3. ई मैक (आई) लि., बम्बई,
4. सेक्मरिया कैमिकल्स, बम्बई,
5. मैसर्स शासन, इग्स, मद्रास।

5. लोक सुनवाई में याचिकाकर्ता एवं आयातकों द्वारा किए गए मौखिक आत्मनिवेदन को लिखित रूप में लिया गया तथा अन्य पक्षों को उपलब्ध कराया गया। इन आत्मनिवेदनों पर आयातकों तथा याचिकाकर्ता की टिप्पणियां मिली हैं। दिनांक 25-5-1993 को आयोजित लोक अदालत में अपने विचार रखने के लिए आयातकों, निर्यातकों एवं याचिकाकर्तियों को एक और अवसर दिया गया। किन्तु, इस सुनवाई में केवल याचिकाकर्ता ही उपस्थित हुए। मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित करवाकर अन्य पक्षों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया गया।

याचिकाकर्तियों के विचार

6. प्रारम्भिक निष्कर्षों के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्तियों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:—

(1) यह कि नामोद्घिष्ट प्राधिकारी द्वारा बताई गई 107/- रुपये प्रति किग्रा. की उचित बिक्री कीमत सही नहीं है; यह कि निश्चित क्षमता उपयोगीकरण के जो सम्पूर्ण उद्योग के लिए 90% से अधिक नहीं हो सकता है के आधार पर यह कीमत वास्तव में 122/- रुपये प्रति किग्रा. होनी चाहिए और यह कि तदनुसार ही पाटनरोधी शुल्क में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

(2) यह कि, जांच पड़ताल की अवधि के दौरान औसत उतराई कीमत के बजाय जांच पड़ताल की समाप्ति पर क्षतिग्रस्त माल की गणना के लिए नवीनतम प्रचलित कीमत को लिया जाना चाहिए।

(3) यह कि, क्षति निर्धारण के संबंध में "व्यापार और तटकर पर आम करार की धारा 6 के करार पर कार्यान्वयन की धारा 3 की पाद टिप्पणी के जरिए प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार क्षति, बणों कि अन्यथा, विशेषीकृत न की गई हो, का अर्थ होना स्वदेशी उद्योग की भौतिक क्षति..." और इसलिए क्षति की सीमा की गणना उद्योग औसत आंकड़ों के आधार पर न कि उद्योग की सर्वाधिक सक्षम इकाई के संबंध में आंकड़ों पर विचार करते हुए, की जानी चाहिए।

(4) यह कि वास्तविक बिक्री कीमत और उचित बिक्री के बीच तुलना में उद्योग को होने वाली क्षति की बेहतर तस्वीर मिल सकती है और इसलिए उसी पर विचार किया

जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जब केवल आयातित सामग्री खरीदता है, तब कोई बिक्री कर देय नहीं होता है, जबकि, घरेलू उद्योग द्वारा उसी बिक्री पर बिक्री का देय होता है। चूंकि घरेलू उद्योग चीन द्वारा प्रस्तुत आईबीबी की सदैव गिरते वाली कीमतों का सामान करने के लिए बाध्य है इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा बेची गयी आईबीबी की औसत बिक्री कीमत, बिक्री कर तत्व के कारण चीनी आईबीबी की उतराई कीमत से हमेशा कम होगी।

(5) यह कि, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन मूल्यह्रास दरों की गिरती हुई प्रवृत्ति के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में परिवर्तन आया है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कंपनी अधिनियम के अनुसार वार्षिक लेखापत्रों में मूल्यह्रास की न्यूनतम दरें दी हैं, इस तरह की मूल्यह्रास दरें जिसमें सयंत्र की कार्यवधि 19 वर्ष मानते हैं, से तथार्थ स्थिति का पता नहीं चलता है। विभिन्न तथ्यों जैसे—सर्पित टेनर—मेड—मंयंत्र, अप्रचलन का खतरा, कैटालिस्ट की अलवाप्ताई प्रवृत्ति के कारण क्षय की सीमा, तथा टूट-फूट, के कारण एक सयंत्र की प्रभावकारी कार्यवधि 6 से 7 वर्ष में अधिक नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता ने एक सनदी अभियन्ता या एक प्रमाणपत्र संलग्न किया है कि दोनों याचिकाकर्तियों के लिए सयंत्र की प्रभावकारी कार्यवधि लगभग 9 वर्ष है।

इसके अतिरिक्त, इस बात का विरोध किया गया है कि मानक कीमत निर्धारित हेतु, विंतीय लेखा उद्देश्य के लिए दरें होते हुए भी, पुरानी मूल्यह्रास दरें ही गृहण की जाएं।

(6) यह कि आई बी बी की कीमत 114/- रुपये प्रति किग्रा. मानकर इबूप्रोफीन की डीपीसी ओ (औषध कीमत नियन्त्रण आदेश) कीमत को प्रथम बार वर्ष 1989 के दौरान संशोधित किया गया था। चीन द्वारा आईबीबी की डम्पिंग के कारण आईबीबी की उतराई कीमत क्रमिक रूप से कम होकर 86/- रुपये प्रति किग्रा. रह गयी। याचिकाकर्ता ने बताया कि डीपीसी ओ के लिए अनुमानित कीमतों से औसत उतराई कीमत कम होने के कारण इबूप्रोफीन विनिर्माताओं ने, स्वदेशी आईबीबी विनिर्माताओं की तुलना में, अनुचित लाभ कमाया है।

(7) यह कि प्रारम्भिक निष्कर्षों में सोची गयी यू.एस.डी. की 2603 प्रति एमटी की सामान्य कीमत याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रारम्भिक प्रार्थनापत्र में प्रदत्त यू.एस.डी. की 4642 पीएमटी कीमतों की तुलना में अत्यधिक कम है।

प्रतिवादी का दृष्टिकोण

7. प्रारम्भिक निष्कर्षों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने निम्नलिखित सुद्धे उठाए हैं:—

(1) यह कि भारतीय विनिर्माताओं ने यू. के. को भी उसी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्तर पर आईबीबी का निर्यात किया है जिसमें सम्पुष्ट होता है कि आईबीबी की प्रचलित बाजार कीमत चीन के आईबीबी की कीमतों के समरूप है

और भारतीय बाजार में चीन द्वारा न्यूनतम कीमतों पर कोई डम्पिंग नहीं की गई है।

(2) चीन के कीमत आंकड़ों के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नहीं होगा कि भारत में लागत कीमत से कम पर वस्तुओं को उभर किया गया है। यह अनुमान लगाना एक भूल होगा कि कच्चे माल और अन्य इनपुटों के खपत मानदण्ड भारतीय विनिर्माताओं के स्तर पर हैं।

(3) उस एफ ओ बी कीमत, जिस पर चीन से आई बी बी का आयात किया जा रहा है तथा भारत में विनिर्मित आई बी बी की फैक्टरी-बाह्य कीमत के बीच के अन्तर के मूल्य को इस तथ्य से देखना है कि विभिन्न टैमिनकल समस्याओं जिसमें कैंटालिस्ट के आयात में दिक्कत शामिल हैं जिससे आई बी बी की उत्पादन लागत बढ़ी है, के कारण भारतीय आई बी बी विनिर्माता अधिकतम क्षमता उपयोगीकरण सहित सतत उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

(4) यह कि पाटनरोधी शुल्क की प्रस्तावित उगाही अर्थव्यवस्था में सुधार की अनुमति के लिए आयात शुल्क कम करने के उद्देश्य को निष्प्रभावी कर देगी।

(5) यह तथ्य, कि भारतीय आई बी बी उत्पादकों को उचित बिक्री कीमत से कम पर बेचना पड़ा है, इस मूल बिन्दु को छोड़ देता है कि कर्गों और शुल्कों, जिनका प्रपाती प्रभाव होता है, की बहुस्तरीय उगाही के कारण घरेलू बाजार में कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में निश्चित रूप से अधिक होंगी। यदि सरकार भारतीय आई बी बी विनिर्माताओं को संरक्षण देने और क्षतिपूर्ति करने को उत्सुक है तो आई बी बी के विनिर्माण में काग आने वाले कच्चे माल पर लगे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य कर्गों में राहत देना अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा।

(6) यह कि उन मामलों का संबंध है जहां आई बी बी का आयात अग्रिम लाइसेंस पर होता है, पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों और मुक्त व्यापार जोन में आई बी बी के प्रयोगकर्ता पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं।

(7) यह कि, दिनांक 31-3-1994 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार एक याचिकाकर्ता कंपनी मैसर्स बिनाटी आर्गनिक्स ने 50 लाख रुपये का लाभ कमाया है। इसके अलावा उन्होंने 100% से अधिक क्षमता उपयोग की उपलब्धि प्राप्त की है।

(8) यह कि, चीन ने मैसर्स कोरिया कैम. टेक. कं. लि. कोरिया को आई बी बी का निर्यात भारत में आयात की कीमतों से कम कीमत पर किया है। इसलिए यह आरोप लगाना वास्तव में असत्य है कि कीमतों में कमी भारत में घरेलू उत्पादकों को स्वारस्यिक क्षति पहुंचाने के लिए की गयी है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों और प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बिन्दुओं की जांच की है। उनका विवरण क्रमबद्ध रूप से नीचे दिया गया है:—

(1) प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया यह तथ्य कि याचिकाकर्ता भी चीन की कीमतों की समतुल्य कीमतों पर आई बी बी का आयात कर रहा है, जांच से संबंधित नहीं है। फिर भी, भारतीय आई बी बी विनिर्माता संघ ने श्रेणीबद्ध रूप से अपने उत्तर में बताया है कि उनके किसी सदस्य ने आई बी बी का निर्यात नहीं किया है।

(2) चूंकि ने तो किसी निर्यातक ने सहयोग दिया है और न ही प्रस्तावली का उत्तर दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कस्टम्स टैरिफ एक्ट की धारा 9(क) (2) के अनुसार आई बी बी की उत्पादन लागत के संबंध में भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किया गया है।

(3) यह दावा कि भारतीय आई बी बी विनिर्माता इष्टतम स्तर पर प्रचालन नहीं कर रहे हैं, सही प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत लागत आंकड़ों के अध्ययन में यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग 92% से अधिक भारित औसत आधार के क्षमता उपयोग पर कार्य कर रही है जिसे अन्तः इष्टतम नहीं माना जा सकता है।

(4) किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क उगाहने का उद्देश्य डम्प किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाना है।

(5) प्रतिवादियों द्वारा दिया गया यह तर्क कि सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं अन्य कर्गों में कमी करके घरेलू उद्योग की क्षतिपूर्ति कर सकती है, व्यवहार्य नहीं है। वास्तव में, डम्पिंग मार्जिन का निर्धारण निर्यात कीमत तथा कर रहित अर्थात् फैक्टरी बाह्य सामान्य मूल्य की तुलना करके किया जाता है।

(6) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा ई पी जेड में स्थित इकाइयों अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात से पूर्णतया अलग स्तर पर हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि डी ई ई सी सामग्री पर दिया गया अन्तिम पाटनरोधी शुल्क वापसी नियमों के अनुसार वापसी के रूप में लौटाया जानकता है।

(7) पाटनरोधी उपायों की मात्रा के निर्धारण में याचिकाकर्ता कम्पनियों के कार्य परिणामों की ध्यान में रखा गया है और तदनुरूप पाटनरोधी शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(8) यह तथ्य कि चीन ने मैसर्स कोरिया कैम. को आई बी बी का निर्यात भारत में आयात की कीमतों से कम कीमत पर किया है, जांच पड़ताल के संगत नहीं है क्योंकि पाटन का निर्धारण करने के लिए भारत में निर्यातित वस्तुओं

की कीमत तथा सामान्य कीमत को ही संगत माना जा ता है ।

(9) याचिकाकर्तियों के मुख्य वाद निम्नलिखित हैं : उत्पादन लागत और उचित बिक्री मूल्य का निर्धारण उद्योगों से समग्र रूप में एकत्रित अभिप्रमाणित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है । चार्टर्ड इंजीनियर के मूल्यांकन के अनुसार, हास दर संयंत्र के आर्थिक जीवन के आधार पर स्वीकृत किया गया है । याचिकाकर्ता की यह शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती कि जांच अवधि के अन्त में पाटन माजिन और उससे होने वाली क्षति की गणना के लिए नवीनतम प्रचलित कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि नोच पैरा-11 में सामान्य मूल्य की जांच अवधि के लिए औसत मूल्य के रूप में माना गया है और इसलिए उस अवधि के दौरान औसत निर्यात मूल्य से तुलना की जाएगी ।

9. दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना के पैराग्राफ 5 से 10 में बताई गई वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10. कस्टम टैरिफ (इन मदों पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियम, 1985 के नियम 16 के अनुसार अन्तिम निष्कर्ष जांच शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाने चाहिए । तथापि, प्रारम्भिक निष्कर्ष इच्छुक पक्षों से जरूरी प्रमुख जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब तथा उनका अपने मामले की पैरवी करने के लिए पर्याप्त समय देने के उपरान्त मामलों के शुरू करने की तारीख से पर्याप्त समय (लगभग 8 महीने) के बाद प्रकाशित किए जा सकते हैं । परिणामस्वरूप, ऊपर उल्लिखित नियम 16 के अनुसार सरकार ने अन्तिम निष्कर्षों के लिए समयवृद्धि प्राप्त कर ली गई थी ।

#### सामान्य मूल्य

11. सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है क्योंकि चूंकि चीन की गैर बाजार अर्थ व्यवस्था है इसलिए सामान्य व्यापार में चीन में आई बी डी की न तो घरेलू कीमतें और न ही चीन में किसी अन्य तृतीय देश का उत्पाद की तुलनीय उच्चतम कीमतें उपलब्ध थीं ।

12. चीन में निर्यातकों की अपेक्षाकृत जानकारी उपलब्ध कराने तथा अपने विचार देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था । चूंकि किसी भी निर्यातक ने जानकारी नहीं दी है और न ही दिनांक 6-2-1995 एवं 25-5-1995 की दो सार्वजनिक मन्वाइयां में अपने विचार व्यक्त करने के अवसर का लाभ उठाया इसलिए अधि-विनियमों के उपबंध 14 के अन्तर्गत प्राधिकारी ने आई बी डी की उत्पादन लागत के संबंध में भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निम्न किया ।

13. सामान्य मूल्य के उद्देश्य के लिए आई बी डी की उत्पादन लागत निम्नानुसार निकाली गयी : कच्चे माल के लिए (1) सरकार द्वारा शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत विनिर्धारित स्टैंडर्ड निवेश-उत्पादन एवं मूल्यवर्धन मानदण्ड (2) याचिकाकर्ता के स्टैंडर्ड मानदण्ड (3) याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक प्राप्तियां (4) चीन की एक फर्म द्वारा अपनी एक परियोजना में गारन्टी शुदा मानदण्डों में से सर्वोत्तम मात्रात्मक मानदण्ड प्रयोग किए गए । कच्चे माल की लागत सामग्री की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (सीमा शुल्क के बिना से मानदण्डों को बढ़ाकर निकाली गयी । अन्य लागत भारत में सबसे अधिक कुशल इकाई से ली गई है ।

#### निर्यात कीमत

14. याचिकाकर्ता ने प्रारम्भिक निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डम्पिंग की माजिन के निर्धारण के लिए प्रयुक्त निर्यात कीमत उच्चतर प्रतीत होती है, हालांकि याचिकाकर्ता कम्पनी ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि उन्हें अपनी बिक्री कीमतें चीन गणराज्य से आयातित आई बी डी की नवीनतम प्रचलित कीमतों के आधार पर रखनी पड़ती हैं, न कि जांच अवधि की औसत कीमत के आधार पर, इसलिए डम्पिंग माजिन के आकलन के लिए तथा क्षति निर्धारण के लिए कीमतों पर इसने प्रभाव को इस रूप में लिया जाना कि यह वह कीमत थी जिस पर जांच पड़ताल अवधि की समाप्ति पर भारत में सामग्री का आयात किया गया था । चूंकि जांच अवधि के लिए सामान्य कीमत को औसत माना जाता रहा है, निर्यात कीमत की सामान्य मूल्य से तुलना करने के लिए निर्यात कीमतों को भी औसत के रूप में माना गया है । जांच अवधि के दौरान निर्यात कीमतों का निर्धारण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय तथा भारतीय सीमा शुल्क विभाग से उपलब्ध आंकड़ों, जिन्हें विश्वसनीय माना गया, पर आधारित उत्पाद के लिए वास्तव में प्रदत्त कीमतों के आधार पर किया गया और इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि निर्यात कीमत में और संशोधन की जरूरत नहीं है । प्राधिकारी दिनांक 10-8-1993 की अधिसूचना के पैरा 13 में दी गई बातों को सम्पूर्ण करता है ।

15. संगत आंकड़े उपलब्ध कराने के प्राधिकारी के अनुग्रेह पर किसी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया और अन्तिम निष्कर्षों के बाद किसी भी आयातक ने और आंकड़े नहीं दिए । इसलिए प्राधिकारी ने 30 अगस्त, 1994 की अधिसूचित अन्तिम निष्कर्षों के पैरा 12 में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए वही तरीका अपनाया ।

#### तुलना

16. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना के लिए अपनाया गए तरीकों, जैसा कि अन्तिम निष्कर्षों में अपनाया गया है, कि पुष्टि कर दी गयी है ।

## अन्तिम निष्कर्ष

17. प्राधिकारी भारतीय उद्योग तथा अन्य सभी पक्षों के हित पर विचार करने एवं दिनांक 30 अगस्त, 1994 को अधिसूचित प्रारम्भिक निष्कर्षों में यथा उल्लिखित क्षति एवं उसके आकस्मिक मामलों से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि (i) पी आर सी के निर्यातकों ने भारत में आईबीबी का सामान्य मूल्य के कम पर निर्यात किया है (ii) भारतीय उद्योग को भौतिक क्षति हुई है, तथा (iii) यह कि डम्प किए गए आयात के भारतीय उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

18. विभिन्न पक्षों के विचारों पर विचार करते हुए नामोदिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले में निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य तथा डम्पिंग का निर्धारण निम्नवत् किया है :—

	यूएस डी/ पीएमटी.	रुपया/मि टन
सामान्य मूल्य	2603	81,995
निर्यात कीमत	1834	57,771
डम्पिंग मार्जिन	769	24,224
औसत सोसाईएफ मूल्य के % के रूप में डम्पिंग का मार्जिन	39.5%	

19. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या डम्पिंग मार्जिन से कम शून्य क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इस उद्देश्य के लिए, चीन के आयात की औसत उतराई कीमत का उद्योग ने प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आकस्मिक घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से तुलना की गई। यह अन्तर डम्पिंग मार्जिन से कम था और तदनुसार प्राधिकारी ने निश्चय किया कि, डम्पिंग मार्जिन से कम का पाटनरोधी शुल्क डम्प किए गए आयात के क्षति प्रभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

20. इसलिए, प्राधिकारी सिफारिश करना है कि चीन मूल के आईबीबी के आयात पर 10.634 रुपये प्रति एमटी की दर से अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए जो भारतीय कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अध्याय 29 के अन्तर्गत आता है।

21. यह प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य मूल के आईबीबी के डम्प किए गए आयात द्वारा भारत गणराज्य में घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति के मामले में उपर्युक्त के अध्यधीन, प्रारम्भिक निष्कर्षों को सम्पूर्ण करना है।

डा.वाई.वी. रेड्डी, नामोदिष्ट प्राधिकारी एवं  
अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 1995

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of IBB originating from PR China—Final findings

No. 14/50/93-TPD/ADD—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1982 and the Customs Tariff Rules, 1985, thereof.

## PROVISIONAL MEASURES

1. The Designated Authority as defined under the Rules (hereinafter referred to as Authority) notified preliminary findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Isobutyl Benzene (hereinafter referred to as IBB) originating from China vide notification no. 14/50/93/TPD dated the 30th August, 1994.

## PROCEDURE

2. The Authority addressed a letter to all the companies subject to investigation requesting them to furnish their views on the preliminary findings and to apply to be heard orally and willingness for on site verification of data furnished. A note verbale was also sent on to Embassy of the concerned exporting country in New Delhi forwarding a copy of the preliminary findings with the request that the exporters and the other interested parties may be advised to furnish views on the preliminary findings to the Authority and willingness for verification of data.

3. The Designated Authority has received views on the preliminary findings from the respondents as well as petitioners. Except the importers in India, no exporter from People Republic of China has furnished views on the preliminary findings.

4. An opportunity was also given to exporter, importers and petitioner to express their views on the preliminary findings in a public hearing held on 6th February, 1995. A note verbals were also sent to Delhi office of the Embassy of P. R. of China on 13th January, 1995 requesting them to intimate the exporters concerned to participate in the public hearing. The public hearing was, however, attended only by the representatives of the petitioner domestic industry and the following importers :

1. M/s. Cheminor Drugs, Hyderabad
2. C. Well Drugs Pvt. Ltd., Hyderabad
3. E. Merck (I) Ltd., Bombay
4. Seksaria Chemicals, Bombay
5. M/s. Shasun Drugs, Madras

5. Oral submissions made in the public hearing by the petitioner and importers were obtained in writing and were made available to other parties. Comments on these submissions were received from the importers and petitioner. Another opportunity was also given to importers, exporter and petitioners to present their views orally in a Public hearing held on 25-5-93. However, the hearing was attended only by the petitioners. The oral views expressed were obtained in writing and made available to the other parties for their comments.

## PETITIONER'S VIEW

6. The petitioners in response to the preliminary findings made the following observations :—

- (i) That the Fair Selling Price of Rs. 107/- Kg. arrived at by Designated Authority is not correct; that it should actually be Rs. 122/- Kg. based on certain capacity utilisation which cannot be more than 90%, for the whole industry; and that accordingly there should be increase in the amount of anti-dumping duty.
- (ii) That the latest ruling price at the end of investigation period should be taken for calculating the extent of injurious effect instead of average landed price during the investigation period.

(iii) That as per explanations provided by way of a footnote to Article 3, relating to Determination of injury, of "Agreement on implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade, "injury, shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry..." and, therefore, extent of injury should be calculated on the basis of industry average figures rather than considering the figures pertaining to the most efficient unit of the industry.

(iv) That the comparison of actual selling price and fair selling would give better picture of the extent to which the industry is injured and, therefore, the same may be considered. The petitioner also stated that when buyer buys the imported materials, no sales tax is payable whereas the same is payable on sales by domestic industry. As the domestic industry is forced to downward match the ever decreasing prices of IBB offered by China, average selling price of IBB sold by domestic industry will always be lower than the landed cost of Chinese IBB due to sales tax element.

(v) That mainly due to downward change in depreciation rates under the Companies Act, 1956, the profitability position of domestic industry has changed. Though the petitioner has provided lower rate of depreciation in Annual Accounts according to the Company's Act, such depreciation rates which assume 19 years as life of the plant, does not reflect the true picture. Due to various factors like dedicated tailor-made plant, risk of obsolescence, extent of corrosion due to alkaline nature of catalyst and wear and tear, the effective life of the plant cannot be more than 6 to 7 years. The petitioner has enclosed a certificate from a Chartered Engineer that the effective life of the plant is around 9 years for both the petitioners.

Further, it has been contended that old depreciation rate may be adopted for standard costing notwithstanding the rate followed for financial accounting purpose.

(vi) That DPCO (Durg Price Control Order) price of Ibuprofen was last revised during 1989 by taking price of IBB as around 114/- per kg. Due to dumping of IBB by China, the landed price of IBB has progressively reduced to an average of Rs. 86/- per kg. The petitioner submitted that due to lower average landed price than was considered in the DPCO, the Ibuprofen manufacturers have earned undue profits at the cost of domestic IBB manufacturers.

(vii) That the normal value of USD 2603 pmt. considered in preliminary findings is extremely on lower side as compared to USD 4642 pmt. provided by the petitioner in their initial application.

#### RESPONDENTS VIEW

7. The respondents have made the following points in response to the preliminary findings :—

- (i) That the Indian manufacturers have also exported IBB at the same international price level to UK, which confirms that the prevailing IBB market prices are at par with Chinese IBB prices and there is no dumping at lower prices by China in the Indian market.
- (ii) In the absence of cost data of China, it is unjustified to conclude that goods are dumped into India below cost price. It is erroneous to assume that consumption norms of raw materials and other inputs are on par with an Indian manufacturer.
- (iii) The differential value between the price at which IBB is being imported from China (fob) and the ex-factory price of IBB manufactured in India has to be looked into from the fact that the Indian IBB manufacturers are not in continuous production with optimum capacity utilisation due to various technical problems including difficulty in import of catalyst, which would have pushed up the cost of production of IBB.

(iv) That the proposed levy of anti dumping duty would defeat the very object of reducing the import duties to permit fair play in the economy.

(v) The fact that Indian IBB producers have had to sell below the fair selling price misses the basic point that the price in the domestic market is bound to be more than the international price due to multi stage levy of taxes and duties which has a cascading effect. If the Government is keen to compensate and protect Indian IBB manufacturers, the more realistic approach would be to grant reliefs in Central Excise and other taxes imposed on raw materials used in manufacture of IBB.

(vi) That in so far as IBB is imported against advance licence, there is no warrant to impose antidumping duty as the user of IBB in the 100 per cent EOUs and FTZs are not subject to the anti-dumping duty.

(vii) That according to the Directors Report for the year ended 31-3-94, M/s Vinati Organics, a petitioner company, has made a profit of over Rs. 50 lakhs. Further they have achieved capacity utilisation of more than 100 per cent.

(viii) That China has exported IBB to M/s. Korea Chem. Tech. Co. Ltd, Korea at a price less than the price at which it has been imported into India. Therefore, the allegation that prices have been depressed in order to cause material injury to domestic producers in India is factually incorrect.

#### EXAMINATION BY AUTHORITY

8. The Authority has examined the points made by the respondents and the petitioners. These are dealt below in serialim :—

- (i) The argument adduced by the respondent that the petitioner is also exporting IBB at a price comparable to Chinese prices is not a factor relevant to the investigation. However, Indian IBB Manufacturers Association categorically stated in their reply that none of their members has exported the IBB.
- (ii) Since none of the exporters cooperated or replied to the questionnaire, the normal value was determined on the basis of best available information in India about the cost of production of IBB in accordance with Section 9 (A) (2) of the Customs Tariff Act.
- (iii) The contention that Indian IBB manufacturers are not operating at optimum levels does not appear to be correct. From a perusal of cost data furnished, it is clearly evident that the domestic industry is operating at a capacity utilisation of more than 92 per cent on weighted average basis which cannot be considered as sub-optimal.
- (iv) The object of levy of anti dumping duty on a product is to remove the injury to the domestic industry caused by dumped imports.
- (v) The argument raised by the respondents that the Govt. can compensate domestic industry by means of reduction in Central Excise and other taxes is not tenable. In fact, the dumping margin is determined by a comparison of the export price and normal values at ex-factory level i.e. without taxes.
- (vi) 100% EOU and units in EPZ are entirely on a different footing from imports under Advance Licence Scheme. It has been clarified that final anti dumping duty paid on DEEC material is liable to be refunded as drawback, in accordance with drawback rules.
- (vii) In determining the quantum of anti dumping measures, the working results of the petitioner companies have been taken into account and the anti dumping duty determined accordingly.
- (viii) The fact that China has exported IBB to M/s. Korea Chem. at a price less than the price at which it has been imported into India is not a factor relevant

to the investigation since the price at which the goods are exported into India vis-a-vis the normal value is the only relevant criteria for determining dumping.

- (x) The major contentions of petitioners are considered as follows : The cost of production and fair selling price have been worked out on the basis of actual data collected/verified for the industry as a whole. Depreciation rate has been adopted on the basis of economic life of the plant as per Chartered Engineer's evaluation. Petitioners' contention to consider the latest ruling price at the end of investigation period for working out dumping margin and injury thereto can't be accepted because the normal value derived as per para 11 below is considered as an average for the investigation period and, therefore, is to be compared with average export price during that period.

9. There is no change in the factual position indicated in paragraphs 5 to 10 of Notification dated 30-8-1994.

10. As per Rule 16 of "Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Inquiry) Rules, 1985 final findings are to be completed within one year from the date of initiation of an investigation. However, preliminary findings could be brought out after the lapse of considerable time from the date of initiation of the case (almost 8 months) due to delay in obtaining the necessary vital information from the interested parties and sufficient opportunity provided to them to plead their case. Consequently, for final findings, extension of time as per rule 16 referred to above was obtained from the Government.

#### NORMAL VALUE

11. The normal value has been determined on the basis of best available information as neither domestic prices of IBB in China in the ordinary course of trade nor the highest comparable price of the product from China to any third country, was available as China is a non-market economy.

12. Ample opportunity was given to the exporters in China to provide the required information and to present their views. As none of the exporters furnished information nor availed the opportunity to express their views in the two public hearings on 6-2-1995 and 25-5-1995, the Authority under provision 14 of the Rules supra, decided to determine the normal value on the basis of best available information in India about the cost of production of IBB.

13. Cost of production of IBB for the purpose of normal value has been arrived at as follows : For raw-material, the best of the quantitative consumption norms out of (i) standard input-output and value addition norms specified by the Government under Duty Exemption Scheme, (ii) Standard norms of the petitioner, (iii) Actuals obtained by the petitioner, and (iv) norms guaranteed by a Chinese firm in one of their project has been used. The raw material cost has been arrived at by multiplying the norms by the international price of the material (without Customs Duties). The other costs have been taken from that of the most efficient unit in India.

#### EXPORT PRICE

14. The petitioners while commenting on provisional findings stated that the export price used for calculating the margin of dumping appears to be on higher side though no further proof was provided by the petitioner company. They have also requested that since they are to match their selling prices based on the latest ruling price of imported IBB from People's Republic of China and not on the basis of average price of investigation period, the export price for calculation of dumping margin and its impact on prices to determine

the extent of injury may be taken as that price on which material was imported in India at the end of investigation period. Since the normal value is being considered as average for the investigation period, the export prices have also been considered on an average for comparing export price with normal value. Export prices during the investigation period were determined on the basis of the prices actually paid for the product based on the data available from Directorate General of Commercial intelligence and Statistics and Indian Customs which were found reliable and, therefore, the Authority is of the view that no further revision is required in the export price. The Authority confirms the contents of para 13 of the Notification dated 10-8-1993.

15. None of the exporters responded to the Authority's request to make available the relevant data and no importer submitted further data after provisional findings. The Authority, therefore, adopted the same methodology in arriving at the export price as indicated in para 12 of the provisional findings notified on 30th August, 1994.

#### COMPARISON

16. The methodology adopted for comparison of Normal Value and export price as adopted in the provisional findings are confirmed.

#### FINAL FINDINGS

17. The Authority after considering the interest of Indian industry and all other parties and taking into account the various factors relating to injury and its causal link as indicated in the preliminary findings notified on 30th August, 1994, has come to the conclusion that (i) exporters from PRC have sold IBB in India below normal value, (ii) The Indian industry has suffered material injury and (iii) that the dumped imports caused the material injury suffered by Indian industry.

18. Considering the views of various parties, the Designated Authority determined the export price, normal value and margin of dumping in this case as follows :

	USD	p.m.t.	Rs./MT
Normal Value	2603	81,995	
Export Price	1834	57,771	
Margin of Dumping	769	24,224	
Margin of dumping as %age of average cif value		30.5%	

19. The Authority considered whether duty lower than margin of dumping would be enough to remove the injury. For this purpose, average landed price of the Chinese imports was compared with the fair selling price of domestic industry worked out on the basis of actual data of the industry. This difference was lower than the dumping margin and accordingly, Authority decided that Anti Dumping Duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injurious effect of dumped imports.

20. The Authority, therefore, recommend that final anti-dumping duty of Rs. 10,634 per M.T. (Rupees ten thousand six hundred and thirty four) be imposed on imports of IBB of Chinese origin, falling under Chapter 29 of Indian Customs Tariff.

21. The Authority confirms subject to above the preliminary findings in the case of material injury caused by dumped imports of IBB originating from Peoples Republic of China (PRC) to the domestic industry in Republic of India.

Dr. Y. V. REDDY, Designated Authority and  
Addl. Secy.

